टैबलेट से बचेगा समय रहेगी पारदर्शिता : सीएम

कैबिनेट में टैबलेट लेकर पहुंचे सीएम और मंत्री

15 को खाते में आएगी 1500 रुपये की राशि

मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति की अग्रिम मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति वह शुभ समय है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है. 15 जनवरी को बाबई नर्मदापुरम से लाडली बहनों के खाते में जनवरी माह की 1500 रुपये की किश्त डाली जाएगी.

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. मंत्रालय में कैबिनेट के लिये मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सभी मंत्री भी टैबलेट लेकर पहुंचें. पिछली कैबिनेट में तो उन्हें कैबिनेट की प्रेसी मैनुअल भी दी गई थी, लेकिन इस बार उन्हें टैबलेट में ही एजेंडा मिला.

डॉ यादव ने टैबलेट में ही एजेंडा देखा और निर्णय के बाद सहमति भी जताई. पिछली बार नये वर्ष की पहली कैबिनेट में 6 जनवरी को मंत्रियों को टैबलेट दिये गये थे और उन्हें ई- टैबलेट एप्लीकेशन का प्रजेंटेशन देकर उपयोग का तरीका बताया गया था. अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान डॉ. यादव ने इस पर खुशी जताई और कहा कि इस पहल से पेपरलेस कार्य प्रक्रिया अपनाने, समय की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. सीएम ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से प्रारंभ हुआ है.यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च तक चलेगा. इसमें शासन की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा.इसमें 16 विभागों की 91 योजनाएं/सेवाएं शामिल हैं. यह नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में साथ-साथ चलेगा. प्रथम चरण में 12 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही होगी. अगले चरण में 16 फरवरी से 16 मार्च तक प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन/शेष आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन होगा.

स्वच्छ जल अभियान की सघन मॉनिटरिंग करें मंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार सभी को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य में स्वच्छ जल अभियान आरंभ किया जा रहा है, जो दो चरणों में संचालित होगा. प्रथम चरण 10 जनवरी से 28 फरवरी और द्वितीय चरण एक मार्च से 31 मार्च के मध्य संचालित होगा. आम नागरिकों की पेयजल समस्या के लिये हर मंगलवार को जल सुनवाई की भी व्यवस्था रखी गई है. अभियान के तहत समस्त जल शोधन यंत्र और पेयजल संग्रहण टंकियों की सफाई होगी, जिसकी निगरानी जीआईएस मैप आधारित एप से होगी. पेयजल संबंधी शिकायतों को 181 पर दर्ज करने की विशेष व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को अपने-अपने जिलों में इस अभियान की सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.

तीस लाख किसानों को सोलर पंप मिलेंगे

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि इस वर्ष डिण्डोरी जिले में मध्यप्रदेश राज्य श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी. ग्वालियर में सरसों अनुसंधान और उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जायेगा. डॉ यादव ने कैबिनेट से पहले अपने संबोधन में कहा कि 30 लाख से अधिक किसानों को अगले तीन साल में सोलर पावर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रदेश का सिंचाई रकबा अभी 65 लाख हेक्टेयर है, इसे बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है. कृषक कल्याण वर्ष का कैलेंडर जारी किया गया है. वर्ष भर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन व कुछ अन्य विभाग मिलकर कार्य करेंगे.

15 जनवरी के बाद फिर बढ़ सकती है ठंड

मौसम में थोड़ी नरमी, सर्दी में मिली राहत

18 जनवरी के आसपास तापमान में गिरावट होने की संभावना

भोपाल, 13 जनवरी . पिछले एक सप्ताह की कड़ाके की सर्दी के बाद मौसम में थोड़ी नरमी देखने को मिली है, लेकिन रात में ठंडक अभी भी बनी हुई है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दो दिन मौसम इसी तरह सामान्य रहने की संभावना है. हालांकि, 15 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में बर्फबारी, कोहरा और बारिश की संभावना है, जिससे प्रदेश में हल्के बादल छा सकते हैं और नमी बढ़ सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, 17-18 जनवरी के आसपास तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे सर्दी फिर बढ़ सकती है. इस समय प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है. पिछले तीन-चार दिनों से तापमान में स्थिरता देखी गई है.

बीते दिन अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान में रविवार की तुलना में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अधिकतम तापमान यथावत रहा. पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी भी जिले में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और सभी जिले सामान्य रहे. पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 किलोमीटर की ऊँचाई पर सक्रिय है.

कांग्रेस ने दी कानूनी कदम की चेतावनी

आरोप : फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों पर कार्रवाई नहीं

विशेष संवाददाता

भोपाल,13 जनवरी. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मंगलवार को राज्य सरकार पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों के मामलों में प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अहिरवार ने कहा कि कई फर्जी जाति प्रमाणपत्र ताकतवर लोगों द्वारा बनवाए गए, जिनमें कुछ आईएएस अधिकारियों की कथित संलिप्तता भी सामने आई. उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक मामलों में जांच होने के बावजूद दोषियों को 'क्लीन चिट' दे दी गई, जिससे जांच की निष्पक्षता और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

अहिरवार ने आगे कहा कि प्रदेश में फर्जी एससी प्रमाणपत्रों से जुड़े 223 से अधिक मामले लंबित हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

लगातार हो रही देरी पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रभावित समाज और कांग्रेस पार्टी के पास न्यायिक हस्तक्षेप का रास्ता ही बचा है. उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर फर्जी एससी प्रमाणपत्र धारकों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

मंत्री प्रहलाद पटेल ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचें. इस दौरान उनके साथ विभाग की राज्य मंत्री राधा सिंह भी थीं.

मंत्री और राज्य मंत्री ने पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की शिकायतें और समस्याएं सुनीं और उनका समाधान किया. भाजपा प्रदेश संगठन ने नई व्यवस्था तय की है, जिसके तहत मंत्री रोटेशन के आधार पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और यहां कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनते हैं. पटेल ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन समस्याओं के निराकरण के लिए महीने के दूसरे मंगलवार का दिन मेरे लिए नियत है.

निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज मैंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से मुलाकात की. इस दौरान कुल 69 लोगों ने मुझसे संपर्क कर अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा किए. अधिकांश समस्याएं मेरे विभाग से संबंधित थीं, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए. कुछ समस्याएं अन्य विभागों से संबंधित थीं, जिन्हें संबंधित विभागीय मंत्रियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई.

सीएमएचओ के खिलाफ खोला मोर्चा

एनएसयूआई ने दी आंदोलन की चेतावनी

विशेष संवाददाता

भोपाल,13 जनवरी. राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बदहाल होती जा रही हैं.

निजी और शासकीय दोनों ही स्वास्थ्य संस्थानों में अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं. एक ओर निजी अस्पतालों पर नियमों की अनदेखी के आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है. इन सबके बीच सबसे गंभीर सवाल सीएमएचओ कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे हैं. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मंगलवार को भोपाल के सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा द्वारा जारी एक आदेश का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वर्षों से नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य कर्मचारियों से बाबूगिरी और संवेदनशील प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं.

परमार ने कहा कि फार्मासिस्ट और नेत्र सहायक जैसे तकनीकी कर्मचारियों को नर्सिंग होम और पीसीपीएनडीटी जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं का प्रभारी बना दिया गया है, जबकि उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है. एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने आरोप लगाया कि ऐसे 'गलत प्रयोग' स्वास्थ्य सेवाओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन पर तुरंत रोक नहीं लगी और जिम्मेदारी तय नहीं हुई, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा.

हेमंत खंडेलवाल और हितानंद ने मकरसंक्रांति पर दी बधाई

भोपाल, 13 जनवरी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल तथा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं.

खण्डेलवाल ने कहा कि लोहड़ी का पर्व नई फसल के स्वागत और उत्सव का प्रतीक है. यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य लेकर आए. साथ ही समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव के भाव को मजबूत करने का संदेश भी देता है. उन्होंने मकर संक्रांति को सामाजिक समरसता, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह पर्व जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भावना लेकर आता है. मकर संक्रांति नई ऊर्जा और संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. प्रदेशवासियों के खुशहाल और संतुलित जीवन की कामना करते हुए खण्डेलवाल ने कहा कि ये पर्व केवल उत्सव नहीं हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने और समाज को एक सूत्र में बाँधने का अवसर भी प्रदान करते हैं.

हाईकोर्ट ने हत्या की सजा बरकरार रखी

पत्नी की हत्या का मामला

7 चोटों से स्पष्ट हुआ हत्या का इरादा

जबलपुर,13 जनवरी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतिका के शरीर पर सात चोटों के निशान पाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपी ने हत्या के इरादे से हमला किया था.

हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की युगलपीठ ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया. उमरिया निवासी शंकर बैगा ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील में कहा गया कि बैगा समुदाय का सदस्य होने के कारण और शराब पीने की स्थिति में उसने पत्नी सुखबंती के साथ 14 जनवरी 2019 को शराब का सेवन किया. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने डंडे से पत्नी पर हमला किया. पत्नी दो दिन बाद, 16 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई. घटना के बाद पाली पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की. अपील में आरोपित ने तर्क दिया कि वह घटना के समय नशे में था और हत्या के नतीजे को समझने की स्थिति में नहीं था. उसने हत्या का इरादा नहीं किया था. उसने सिर्फ डंडे से मारपीट की थी और कोई घातक हथियार प्रयोग नहीं किया.

युगलपीठ ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार अपीलकर्ता अपनी पत्नी पर हमला कर रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाली महिला बीच-बचाव के लिए आई थी, जिस पर आरोपी ने मारने की धमकी दी और थप्पड़ मारा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि मृतिका नशे में नहीं थी. रिपोर्ट में सात चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या का इरादा सिद्ध होता है. इसी आधार पर कोर्ट ने अपील खारिज कर दी.

अनारक्षित टिकट पर 3% डिजिटल लाभ

14 जनवरी से 14 जुलाई तक सुविधा उपलब्ध होगी

भोपाल, 13 जनवरी . भारतीय रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और यात्रियों को सीधे आर्थिक लाभ देने के लिए रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट पर 3 प्रतिशत बोनस छूट की सुविधा लागू करने की घोषणा की है.

यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक आधार पर उपलब्ध होगी. पहले यह लाभ केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर ही मिलता था, लेकिन अब सभी स्वीकृत

डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि पर भी मिलेगा. इससे यात्रियों को अनारक्षित टिकट बुकिंग में प्रत्यक्ष बचत होगी. यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी देने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. यह पहल कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित करने के साथ डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती प्रदान करेगी.

102 करोड़ का ऑरिजिनेटिंग राजस्व किया अर्जित

भोपाल. महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में दिसम्बर माह में पूरे पश्चिम मध्य रेल ने 572 करोड़ 57 लाख रुपए का माल यातायात से ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के 489 करोड़ 01 लाख रुपए की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है. रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य 532 करोड़ 05 लाख रुपए से यह लगभग 8 प्रतिशत अधिक है. भोपाल मंडल ने इसी दौरान 102 करोड़ 05 लाख रुपए का ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया. माल यातायात बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाकर खंड की क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार किया गया है. गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और साइडिंग का विस्तार, मालगाड़ियों के डिटेंशन में कमी, टर्मिनल वर्किंग में सुधार और माल गोदामों में चौबीस घंटे लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा लागू की गई है.

विशेष रूप से दैनिक यात्री और उपनगरीय क्षेत्र के लोग इस सुविधा से लाभान्वित होंगे. सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के उपयोगकर्ता अपनी पहचान से लॉग इन कर सकते हैं. ऐप पर अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन-स्टेशन जानकारी और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

समय में काम नहीं, तो कार्रवाई होगी

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए मंत्री सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग में एक तकनीकी विंग गठित करने के निर्देश दिए. यह तकनीकी विंग विभागीय जांच दल के रूप में कार्य करेगा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं मानकों की नियमित जांच करेगा. उन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस का मजबूत सिस्टम विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी वर्किंग एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं.

उन्होंने कहा कि यदि कोई एजेंसी तय टाइमलाइन में कार्य पूर्ण नहीं करती है, तो उसके विरुद्ध निर्माण अनुबंध की शर्तों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मप्र पुलिस हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पीआईयू, आईडीए, बीडीए, यूडीए और भवन विकास निगम सहित विभिन्न वर्किंग एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि मासिक आधार पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा स्टेप-बाय-स्टेप और मंथ-बाय-मंथ लक्ष्य तय कर निर्माण कार्य पूरे किए जाएं. मंत्री ने कहा कि प्रत्येक एजेंसी अपनी कार्ययोजना स्पष्ट रूप से विभाग को उपलब्ध कराए.

मध्यप्रदेश में अशासकीय स्कूलों की मान्यता-नवीनीकरण की तिथि बढ़ी

भोपाल. मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित अशासकीय स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की तिथि को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण अथवा नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा. पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी लेकिन तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं के मद्देनजर इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी किया गया है.

दूषित जल मामला ▶ 50 दलों ने किया घर-घर सर्वे, 3 दिन में 16 हजार की जांच

आईसीयू में अभी भी 8 मरीज भर्ती

03 वेंटिलेटर पर, 436 भर्ती में से 403 डिस्चार्ज

नव भारत न्यूज

इंदौर, 13 जनवरी. भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली स्वास्थ्य समस्या को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है.

समाचार लिखे जाने तक 436 मरीज अस्पतालों में भर्ती किए, जिनमें से 403 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं. फिलहाल 33 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, इनमें 8 मरीज आईसीयू में हैं और 3 की हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर उपचार जारी है.

मंगलवार को प्रभावित क्षेत्रों में 50 दलों ने घर घर सर्वे किया. 187 सदस्यों की टीम ने महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की. रक्तचाप, शुगर और एनीमिया की जांच पर विशेष फोकस रखा. पिछले तीन दिनों में 16,208 लोगों की जांच की गई, जिसमें 278 लोगों में उच्च रक्तचाप और 161 लोगों में मधुमेह के लक्षण पाए. चिन्हित मरीजों को हेल्थ कार्ड देकर आगे की जांच और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में जाने की सलाह दी. वहीं भागीरथपुरा क्षेत्र की ओपीडी में मंगलवार को 109 मरीज पहुंचे, जिनमें 5 डायरिया के मरीज शामिल थे. किसी भी मरीज को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी. क्षेत्र के निवासियों को हेल्थ कार्ड वितरित किए, जिनमें उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी प्रमुख सूचकांक दर्ज किए हैं. आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर लोगों को पानी उबालकर पीने, साफ सफाई रखने और चल रहे इलाज की दवाइयों का पूरा कोर्स लेने की समझाइश दी.

सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं और 24म7 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है. गंभीर मरीजों को एमवाय अस्पताल, अरविंदो अस्पताल तथा बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में रेफर किया जा रहा है. निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को भी निःशुल्क जांच, उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में परेशानी न हो.

जमीनी विवाद में गोलीबारी

02 लोग गंभीर रूप से घायल

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

भिंड,13 जनवरी. जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हुआ. विवाद की शुरुआत खेत में खाद डालने को लेकर हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस और मारपीट हुई. इस दौरान एक युवक बंदूक लेकर मौके पर पहुंचा और दो राउंड फायर किए.

घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल दो लोगों कल्ली पुत्र केशव सिंह गुर्जर और सत्यभान सिंह गुर्जर को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. वहीं, अन्य घायलों को गोहद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद जमीन के अधिकार और खेती को लेकर हुआ था. घटना के बाद इलाके में तनाव देखा गया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

पेज एक का शेष

पांच हजार करोड़ के कर्ज से सुधारेंगे शहरों की सेहत

इन विद्यालयों की स्थापना के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये भी मंजूर किये गये हैं, द्वितीय चरण के प्रस्तावित विद्यालयों की क्षमता एक हजार से अधिक होगी. पहले चरण में 275 विद्यालय मंजूर किये गये थे. मप्र स्पेसटेक नीति-2026 लागू होगी: कैबिनेट ने मप्र स्पेसटेक नीति-2026 लागू किये जाने की स्वीकृति दे दी है. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानिक विश्लेषण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी. प्रदेश में आगामी 5 वर्ष में 1 हजार करोड़ का निवेश और लगभग 8 हजार का रोजगार सृजन होगा. इस पर अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रुपये आयेगा.

यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

- सहायक उप निरीक्षक स्व. रामचरण गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि स्वीकृत.
- ग्वालियर व्यापार एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 फीसदी छूट मिलेगी.
- प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति. स्वीकृति अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही परियोजना के तहत सोलर-सह चार घंटे 300 मेगावाट, सोलर सह छह घंटे 300 मेगावाट एवं सोलर-सह 24 घंटे 200 मेगावाट विद्युत प्रदाय की सिंगल साइकिल चार्जिंग आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना साकार होगी. इस परियोजना से राज्य में पीक डिमांड के समय भी सस्ती, स्वच्छ एवं भरोसेमंद विद्युत उपलब्ध हो सकेगी.